

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्रसापारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशन

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 166] नई दिल्ली, शनिवार, मई 2, 1970/वैशाख 12, 1892

No. 166] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 2, 1970/VAISAKHA 12, 1892

इस भाग में अलग पृष्ठ संख्या को जाती है जिसमें कि वह यसका सक्रियता से अलग हो रहा वा प्राप्त हो रहा।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May 1970

S.O. 1628.—Whereas a vacancy has occurred in the Narmada Water Disputes Tribunal, constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Irrigation and Power No. S.O. 4054 dated the 6th October, 1969, consequent on the resignation of Shri Justice G. C. Mathur;

And whereas the Chief Justice of India has nominated Shri Justice E. Venkatesam of the Andhra Pradesh High Court to fill the said vacancy under section 5-A of the Inter-State Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 4, read with section 5-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the said notification, namely:—

In the said notification, for item (iii), the following item shall be substituted, namely:—

"(iii) Shri Justice E. Venkatesam, Judge of the Andhra Pradesh High Court—Member."

[No. 12/6/69-WD.]

By order and in the name
of the President of India.

V. V. CHARI Secy.

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 1970

का० आ० 162 :—यतः भारत रक्कार के सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० अ० 4055, तारीख 6 अक्टूबर, 1969 द्वारा गठित नमंदा ज विवाद अधिकरण में एक रिक्ति, न्यायपूर्ति श्री जी० साँ० माथुर द्वाग दर्शाय करने पर्याम म वल्प, कुई है;

और यतः भारत के मुख्य न्यायपूर्ति ने अन्तर्राजिक जल विव.व अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 5-के अधीन उक्त रिक्ति को भरने के लिए आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायपूर्ति श्री ई० वेंटेसम का नामनिर्दिशित किया है;

यतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5-के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में एतद्वारा निम्नलिखित संश धन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में अन्तिम भव (3) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(3) श्री जस्टिस ई० वेंटेसम, उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश के न्याय वीश सदस्य ।”

[सं० 12/6/69-डब्ल्यू० डी०]

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से और उन के ताम में,

वी० वी० चारि, सचिव ।